



हम तीन तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है और तीसरा अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है।
-कन्ययूथियस

मूल्य
₹ 3/-

जिद...सच की

● वर्ष: 11 ● अंक: 330 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार 7 जनवरी, 2026

आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को... 7 महाराष्ट्र निकाय चुनाव के प्रचार... 3 बीजेपी-चुनाव आयोग का गठबंधन... 2

बुलडोजर की कार्रवाई और एक्वआई आखिर क्यों हो रही है अशांत दिल्ली

» दो दिन, दो घटनाएं
सुलगते सवाल

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली अशांत है, सवालों के घेरे में है और हालिया कार्रवाईयों से दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठना शुरू हो गये हैं। जेएनयू की घटना के ठीक दूसरे दिन तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए इक्टडा हुई 32 जेसीबी मशीनों की अफवाहों के बादल से ईंट, पत्थर के बाद लोगों पर बरसी पुलिस की लाठियों ने हालात बेकाबू कर दिये और एक नई बहस को जन्म दे दिया। एक्वआई पर घिर रही रेखा सरकार को फिलहाल फौरी राहत मिलती दिखाई दे रही है।

नीति निर्धारक चाहते भी यही थे गैस चैंबर बनती दिल्ली की ब्रांड को राहत मिले मौसम ठीक होगा तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। भारत के विपक्षी राजनीतिक दल सवाल यही उठा रहे हैं कि दिल्ली में लगातार दो दिन दो प्रयोग किये गये क्या वह माहौल बदलने के लिए हुए? क्योंकि अवैध अतिक्रमण इससे पहले भी हटाये गये हैं लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुर्कमान गेट के आसपास हटाये गये।



तुर्कमान गेट सिर्फ एक घटना नहीं

1976 का तुर्कमान गेट कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह सत्ता की घबराहट का प्रतीक थी। आपातकाल के दौर में शहर को सुंदर बनाने के नाम पर गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गयीं। कानून व्यवस्था का बहाना बना लेकिन असल में सवाल पूछने वालों को कुचाल दिया गया। तुर्कमान गेट इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह बताता है कि जब सत्ता असहज होती है तो सबसे पहले हथियारे के लोगों पर वार होता है। आज जब उस घटना को फिर से बहस में लाया जाता है तो यह सिर्फ इतिहास नहीं होता यह एक संदेश होता है।

जेएनयू के सवालों से डरती सत्ता?

हर दौर में हर सरकार के लिए जेएनयू असहज रहा है। क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं। यहां सहमति अनिवार्य नहीं होती। यहां तर्क इतिहास और विचार टकराते हैं। जेएनयू के नारे कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि उन्हें किस वक्त और किस अंदाज में उछला जाता है। जब

बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए जब महंगाई पर सवाल उठने चाहिए जब प्रदूषण पर जवाबदेही तय होनी चाहिए तब अचानक जेएनयू का वीडियो वायरल हो जाता है। तब अचानक देशभक्ति की परीक्षा शुरू हो जाती है। तुर्कमान गेट और जेएनयू को एक साथ देखने का मतलब यह नहीं

कि हालात वही हैं। लेकिन यह जरूर है कि सत्ता का व्यवहार वही पुराना है। तब भी गरीब आसान निशाना थे। आज भी हैं। तब भी सवाल पूछने वाले असुविधाजनक थे। आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि अब बुलडोजर के साथ कैमरा भी है। और आदेश के साथ नैरेटिव भी।

एफआईआर दर्ज 10 हिरासत में

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद तनाव की स्थिति है। पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में करीब 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बहा दी गई है जहां देर रात एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी सीसीटीवी फुटेज और बांडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है।

मलिक मोतासिम खान ने उठाये सवाल

जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्कमान गेट के पास मस्जिद को लेकर मुसलमानों का मानना है कि यह वक्फ की जमीन है और उनकी प्रॉपर्टी है। मस्जिद के नजदीक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दवाखाना, बारात घर और कुरान की तालीम के लिए कुछ कमरे बनाए थे। मस्जिद के साथ उससे जुड़ी हुई एक जगह होती है जहां लोग नमाज के लिए तैयारी करते हैं। मुसलमानों का कहना है कि यह वक्फ की

जमीन है जबकि सरकार का दावा है कि यह सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया गया है। यही असली विवाद है। उन्होंने कहा इतनी जल्दी कार्रवाई की गई? यह प्रशासन की ज्यादाती है। मान लिया जाए कि अवैध अतिक्रमण था लेकिन वहां बने वज्खाने और अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत हो सकती थी। रात को बुलडोजर और ट्रक लेकर आए व सैकड़ों पुलिसवाले खड़े हो गए जिससे दहशत फैली।



जवाब कौन देगा?

दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक और नाम चर्चा में है और वह है सीएम रेखा गुप्ता का नाम। उन पर उठते सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं हैं बल्कि पैसे की बर्बादी और प्राथमिकताओं की विफलता से जुड़े रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं योजनाएं बन रही हैं फाइलें चल रही हैं लेकिन जमीन पर न हवा सुधार रही है न जिंदगी। सवाल यह है कि जब राजधानी गैस चैंबर बन चुकी है तब पैसा किस दिशा में बहाया जा रहा है? और क्यों हर बार बहस को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है? दिल्ली के लोग यह पूछ रहे हैं कि एक्वआई से निपटने के लिए जो बजट आया उसका हिसाब कौन देगा? प्रदूषण से लड़ने के नाम पर हुए खर्च का ऑडिट क्यों नहीं? लेकिन इन सवालों का जवाब देने की बजाय माहौल को गरम किया जा रहा है। भावनाओं से, नारों से और इतिहास की राख से।



हवा जहरीली लेकिन टीवी पर बहसें सुरीली

दिल्ली इस वक्त दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में एक है। एक्वआई जानलेवा स्तर पर है। स्कूल बंद हैं अस्पताल भरे हुए और लोगों को सांस लेना एक चुनौती बन चुका है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर हवा नहीं दिखती। दम घुटता नहीं



दिखता। दिखते हैं तो सिर्फ नारे, विवाद, और उबाल। यह संयोग है?

या रणनीति? जब सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए कि हवा जहरीली

क्यों है समाधान क्यों नहीं है और जवाबदेही किसकी है तब बहस मोड़ दी जाती है राष्ट्रविरोधी नारे की ओर। तब कैमरे पहुंच जाते हैं विश्वविद्यालयों में। तब इतिहास से तुर्कमान गेट निकालकर वर्तमान में फिट कर दिया जाता है।

बीजेपी-चुनाव आयोग का गठबंधन नहीं चलने देंगे : फखरुल हसन चांद

» सपा का पीडीए एसआईआर प्रहरी रखेगा कड़ी नजर

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसको लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। सपा ने चुनाव आयोग व भाजपा पर जोरदार हमला किया है। वहीं आयोग ने कहा है कि जिन वोटरों को इस सूची में संशोधन करवाकर अपने नाम जुड़वाने हैं वे 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आपतियां दर्ज कराएं। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद का कहना है कि समाजवादी पार्टी पीडीए वोटों की सुरक्षा का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एसआईआर प्रहरी है उसने सतर्कता से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाकर पीडीए के वोट को बचाने का काम किया। पीडीए के वोट को बनाने का काम किया।

एसआईआर पर सपा की रणनीति को



लेकर कहा, एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी फॉर्म 6 भरा जाएगा। सपा का एसआईआर पीडीए प्रहरी सतर्कता से इसमें भाग लेगा, और पीडीए के जो वोट बचे हैं उनको बनवाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन को चलने नहीं देगा।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सभी सजग

उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वह जारी रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अभी वह लिस्ट आई है जिन वोटरों के नाम को काटा गया है। वे बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो शहरों और गांवों में बीजेपी को वोट देते थे। समाजवादी पार्टी इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है।

आधार को वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड से लिंक करें

उन्होंने सुझाव दिया कि, अखिलेश यादव ने पहले भी इस बात को उठाया था कि आधार को भले ही आप वैलिड डॉक्यूमेंट न मानिए लेकिन अगर आप आधार को वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड से लिंक कर देंगे तो दूसरी जगह कहीं भी वोट डालने का अधिकार

खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक, आधार से लिंक वोटर लिस्ट होगी तो वह किसी अन्य राज्य में भी वोट नहीं डाल सकेगा, और एक राज्य में भी दो जगह वोट नहीं डाल सकेगा। वह अपना ही वोट डाल पाएगा, दूसरी जगह कहीं वोट नहीं डाल पाएगा।

जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपाई : उमर अब्दुल्ला

» मुख्यमंत्री बोले- वे हर चीज में धर्म को घसीटते हैं

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विजय मर्चेट ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर के शानदार प्रदर्शन के बहाने भाजपा और हिंदू संगठनों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने फुटबॉल टीम चयन विवाद पर कहा, वे हर चीज में धर्म को घसीटते हैं। वे शिक्षा में धर्म को घसीटते हैं। वे खेलों में धर्म को घसीटते हैं। जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। खाने-पीने के बारे में सुझाव देकर तो उन्होंने सारी हद्द पार कर दी हैं। अब क्या बचा है?

मुख्यमंत्री ने जम्मू में पत्रकारों के सवालों पर कहा कि उनकी पार्टी हर खेल को उसके वास्तविक स्वरूप में देखती है। आपको उन लोगों से सवाल पूछने चाहिए जो खेल को राजनीति से जोड़ते हैं। जब हम टीम को देखते हैं, तो हम खिलाड़ियों के धर्म को नहीं देखते। वे धर्म के अलावा कुछ और नहीं देखते। जब फुटबॉल टीम में मुसलमानों की संख्या अधिक थी तो उन्हें उस पर

आरक्षण पर उपराज्यपाल को देना चाहिए जवाब

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब लोकमवज को इस बारे में जवाब देना है। उन्होंने कहा, सरकार ने रिजर्वेशन के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट ने इसे पारित कर उपराज्यपाल को भेज दिया। अब उपराज्यपाल को रिजर्वेशन पर फैसला करना है। लेकिन अभी तक वह से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

आपत्ति थी। जब क्रिकेट टीम में मुसलमानों की संख्या कम हुई तो उन्हें क्रिकेट टीम पर कोई आपत्ति नहीं थी। जब समस्या नहीं बची तो जम्मू को अलग करना चाहते हैं = पिछले कई दिनों से भाजपा व हिंदू संगठन जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर ने इस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उमर ने विरोध करने वालों पर हमला करते हुए कहा, उनके पास अब कोई समस्या नहीं बची है तो वे जम्मू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के अच्छे कामों की अनदेखी करती है : अजित पवार

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी सहयोगी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के संगठन के लिए किए गए अच्छे कामों की कद्र नहीं करती। पवार ने यह बात पुणे शहर के बानेर इलाके से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व पार्षद अमोल बलवडकर का उल्लेख करते हुए कही, जिन्हें भाजपा ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख पवार नगर निकाय चुनाव से पहले पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बलवडकर ने टिकट न मिलने के बाद भाजपा से इस्तीफा दे दिया और राकांपा में शामिल हो गए। पवार ने अपने भाषण में कहा कि राकांपा ने न केवल अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के काम को पहचाना, बल्कि उन्हें चुनाव में टिकट भी दिए। हालांकि पवार ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार में भाजपा के साथ गठबंधन में बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं सिर्फ उन लोगों पर निशाना साध रहा हूँ जो पुणे और पीसीएमसी (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका) में सत्ता में थे, जहां पिछले नौ साल में विकास पटरी से उतर गया।

बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन : अकबरुद्दीन ओवैसी

» पूर्व सीएम व भाजपा नेता एन किरण कुमार रेड्डी को घेरा

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा का शीतकालीन सत्र इन दिनों अपनी तीखी बहसों और राजनीतिक कटाक्षों के लिए चर्चा में है। यहां जोर शोर से पक्ष-विपक्ष की तरफ से राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं।

एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज्य के विभाजन के समय की भविष्यवाणियों को याद करते हुए भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी पर वॉशिंग मशीन वाला तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रेवंत रेड्डी भी अकबरुद्दीन की बात पर हंसते नजर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के विभाजन (2014) के दौर की यादें ताजा की। उन्होंने बिना नाम लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री (एन. किरण कुमार रेड्डी) का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब



भविष्यवाणी की गई थी कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बना तो यहां न बिजली होगी, न पानी और न ही विकास के लिए पैसा। ओवैसी ने कहा, आज देखिए तेलंगाना विभाजन के बाद कितनी अच्छी तरह फल-फूल रहा है। अकबरुद्दीन ने एन किरण कुमार रेड्डी को लेकर कहा कि वे नेता पहले कांग्रेस में थे। अब भाजपा में चले गए। शायद उन्हें जाना ही था, क्यों वॉशिंग मशीन तो अब भाजपा के पास है। इनके अलावा अकबरुद्दीन ने जीएसटी संशोधन, मूसी नदी के पुनरुद्धार और जीएचएमसी के विस्तार जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। राज्य में उसको उचित फंड नहीं मिल रहा है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जेदी



ऐसे नारे ठीक नहीं पर पीछे की वजह भी देखनी होगी : मनोज झा

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे कथित विवादित नारे के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि वह खुद ऐसे नारों के खिलाफ हैं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे की वजह भी देखनी होगी। झा ने कहा कि मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी। मैं ऐसे नारों के खिलाफ हूँ।

मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नारे का समर्थन कभी नहीं करता हूँ। अब इस नारे के पीछे चलते हैं। जो शरजील इमाम को कल बेल नहीं मिली। जो कोर्ट में तर्क दिए गए वह ठीक नहीं लग। बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा



2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के

राजद सांसद ने जेएनयू में नारे पर दी प्रतिक्रिया

50 सालों में देश में इस तरह के नारे 100 बार लगाए गए : हज्जान

सीपीआई (एम) नेता हज्जान मोल्लाह ने कहा कि, पिछले 50 सालों में देश में इस तरह के नारे 100 बार लगाए गए हैं... हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए... नारे लगाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।

एक समूह ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए, सोमवार रात हुए विरोध प्रदर्शन के कथित वीडियो के अनुसार, मोदी और शाह की निंदा करते हुए नारे लगाए गए।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के प्रचार में आई तेजी

कांग्रेस भी पूरे जोश में, यूबीटी शिवसेना व एनसीपी शरदगुट भी तैयार

- » सभी दलों ने एक-दूसरे किए सियासी वार
 - » सभी नगर निगमों के चुनाव 15 को
 - » मराठी अस्मिता पर मनसे की राजनीति आरंभ
 - » भाजपा को पूरी तरह भरोसा जीत उसी की
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क



मुंबई। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ लिया है। भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना व एनसीपी के दोनों गुट व औवैसी की पार्टी समेत सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। राज्य की सत्ता में बैठी महायुति व विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उधर राज व उद्धव के साथ आने से मुकाबला कांटे का हो गया है। भतीजे अजित पवार व चाचा शरद पवार कु छ सीटों पर एक साथ आए हैं। कांग्रेस भी कु छ सीटों पर अपनी मजबूत दवेदारी कर रही है।

इस बीच कु छ सीटों पर महायुति के एकतरफा जीत पर बवाल मचा हुआ है। इन सबों बीच मनसे मराठी के नाम पर भवनात्मक अपील करके जीत हासिल करने के इरादे में हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने एक ऐसा चुनावी वीडियो जारी किया है, जिसने राजनीतिक हलकों के साथ-साथ मराठी समाज के भीतर भी गहरी बहस छेड़ दी है। वीडियो की शुरुआत ही एक चौंकाने वाली पंक्ति से होती है कि अगर आप मराठी हैं, तो यह वीडियो मत देखिए, लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वह मराठी मानुस के भविष्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शुक्रवार (2 जनवरी) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, और इसके समाप्त होते ही महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। निर्विरोध विजयी हुए महायुति के 68 उम्मीदवारों में से 44 भाजपा से, 22 शिवसेना से और दो एनसीपी से थे। हालांकि, अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार (3 जनवरी) को जांच के आदेश दिए।

महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते तो एमएनएस ने उठाए सवाल

राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने सोमवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से संपर्क कर ठाणे नगर निगम और राज्य के अन्य नगर निकायों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों पर रोक लगाने का आग्रह किया। एमएनएस नेता अविनाश जाधव के नेतृत्व में एक पार्टी

प्रतिनिधिमंडल ने एसईसी से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की। एमएनएस के ठाणे और पालघर जिला अध्यक्ष जाधव ने कहा कि जांच एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हों। पार्टी ने ठाणे नगर निगम चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विपक्षी

उम्मीदवारों, जिनमें एमएनएस के उम्मीदवार भी शामिल हैं, या तो पैसों का लालच दिया गया या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे समूह) के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर आघात है।

1999 के बाद पहली बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में

महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। 1999 के बाद यह पहला मौका है जब पार्टी राज्य के नगर निगम चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी तो बीएमसी चुनाव महाविकास अघाड़ी से अलग होकर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की सीटों का गणित- मुंबई- 167 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, ठाणे- 101 सीटों पर दावेदारी, पुणे- 100 सीटों पर जंग, छत्रपति संभाजी नगर- 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पिंपरी चिंचवड- 60 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। शहरों में पूरी तरह अकेले के दम पर लड़ाई! कांग्रेस ने नागपुर, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर में किसी से गठबंधन न करते हुए अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

आंकड़ों के जरिए चेतावनी

वीडियो के अंत में मुंबई में मराठी भाषी आबादी में लगातार गिरावट के आंकड़े दिखाए जाते हैं, जो मनसे के संदेश को और धार देते हैं। 1981- 46 प्रतिशत 2001-39 प्रतिशत, 2011- 35 प्रतिशत, 2025- 30 प्रतिशत, 2035 (अनुमानित) - 25 प्रतिशत। मनसे का दावा है कि अगर यही रुझान जारी रहा, तो आने वाले दशकों में मराठी मानुस अपने ही शहर में अल्पसंख्यक बन जाएगा और यही इस वीडियो का केंद्रीय संदेश है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लंबे समय से कहते आए हैं कि मराठी लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति, रोजगार और अस्तित्व को लेकर सजग रहना होगा। उनका मानना रहा है कि अगर मराठी समाज राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हुआ, तो मुंबई से उसका वजूद धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे के शब्दों में अवसर यह भाव रहा है। मराठी मानुस की पहचान उसकी भाषा, उसका स्वाभिमान और उसका हक है। अगर यह चला गया, तो सब चला जाएगा।

कांग्रेस का वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ तालमेल

लातूर में कांग्रेस ने केवल 5 सीटें वंचित के लिए छोड़ी हैं, बाकी सभी सीटों पर खुद लड़ रही है। नांदेड में वंचित को 20 सीटें दी गई हैं, जबकि शेष सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी को 41 नगर परिषद अध्यक्ष पद पर जीत मिली थी जबकि 1006 पार्षद की सीटें

मिली थी। बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जीत दर्ज की है। पार्टी ने 207 अध्यक्ष पद जीत दर्ज किए थे। वहीं, विपक्षी महाविकास अघाड़ी कुल 44 नगर अध्यक्ष पद ही जीत पाई थी हालांकि, स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने खुद को मुख्य विपक्ष के तौर पर पेश किया है।

अस्तित्व की लड़ाई का आह्वान

मनसे का यह वीडियो सिर्फ एक चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि मराठी समाज के लिए एक चेतावनी और आह्वान माना जा रहा है। पार्टी का संदेश साफ है - अगर मराठी लोग अब भी नहीं जागे, अगर वे आपसी मतभेदों से ऊपर नहीं उठे और अगर उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने का राजनीतिक संदेश नहीं दिया तो 2052 की यह कल्पना हकीकत भी बन सकती है। बीएमसी चुनाव में यह वीडियो मराठी वोटर्स को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश है। मनसे इसे विकास बनाम अस्तित्व की बहस में बदलना चाहती है कि जहां सवाल सिर्फ सड़कों और इमारतों का नहीं, बल्कि मुंबई में मराठी मानुस के भविष्य का है। स्पष्ट है कि बीएमसी चुनाव 2026 में मनसे का यह अभियान मराठी राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ले आया है, और यह तय करना अब मतदाताओं के हाथ में है कि वे इस चेतावनी को सपना समझकर नजरअंदाज करेंगे या भविष्य सुरक्षित करने का संदेश देंगे।

शिवसेना-यूबीटी के आरोप

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि शिवसेना-यूबीटी और एमएनएस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए गठबंधन किया है। संजय राउत ने कहा कि मेरे एक मित्र, जो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, ने कहा कि (दोपहर 3 बजे के बाद फॉर्म स्वीकार करना) उचित नहीं होगा। उन्हें पालक मंत्री ने एक ऐसे लहजे में कहा जो अनुरोध और धमकी दोनों जैसा लग रहा था, कि उन्हें स्थानीय विधायक की बात सुननी चाहिए।

मुंबई के चिड़ियाघर में मराठी मानुस का वीडियो वायरल

वीडियो में वर्ष 2052 की कल्पना की गई है, जहां एक मराठी मानुस मुंबई के चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद दिखाया जाता है। वह खुद अपनी कहानी सुनाता है-कैसे मराठी लोग आपस में ही लड़ते रहे, कैसे विकास के झूठे सपनों में फंसते चले गए और अंततः मुंबई से बाहर खदेड़ दिए गए। वीडियो का कथानक यह



संदेश देता है कि मराठी समाज की

आपसी फूट, राजनीतिक स्वार्थों में

बंटवारा और अस्मिता के मुद्दों की अनदेखी। इन सबका नतीजा यह हुआ कि मराठी मानुस अपने ही शहर में हाशिये पर चला गया। वीडियो में एक अहम मोड़ तब आता है जब वह किरदार कहता है कि एक व्यक्ति था, जो हमें लगातार आगाह करता रहा (राज ठाकरे का भाषण) लेकिन हमने उसकी बात

नहीं सुनी। यह संकेत साफ तौर पर राज ठाकरे की ओर है, जो वर्षों से मराठी अस्मिता, भाषा, रोजगार और जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर चेतावनी देते आए हैं। इसके बाद वह व्यक्ति अचानक नौद से जागता है- और तारीख होती है जनवरी 2026, यानी, अभी भी हालात बदलने का वक्त बाकी है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

खाली प्रचार माध्यम के लिए शहरों को स्मार्ट न बनाएं

66

सरकारों को चाहिए की खाली प्रचार के लिए शहरों को स्मार्ट न बनाएं उन्हें हकीकत में सुदृढ़ करें। दूषित पानी पीने से मौत की घटना देश में कहीं भी हो-शर्मनाक है। इंदौर जैसे शहर में ऐसी घटना का होना और भी चिंता की बात है क्योंकि यह शहर कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा लिए फिरता है।

इंदौर की घटना ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ सड़के चौड़ी कर देने, चमकीले लाइट लगाने व सुंदर फूलदान लगाने से कोई शहर स्मार्ट नहीं हो जाता है। वो दिखने में अच्छा लग सकता है। पर उसके बुनियादी ढांचे में भारी कमजोरी छिपी है। जो स्वच्छता के नाम से सबसे आगे था वह हकीकत में खोखला साबित हो गया जब वहां के पानी की प्रदूषण ने कई लोगों को लील लिया। सरकारों को चाहिए की खाली प्रचार के लिए शहरों को स्मार्ट न बनाएं उन्हें हकीकत में सुदृढ़ करें। दूषित पानी पीने से मौत की घटना देश में कहीं भी हो-शर्मनाक है। इंदौर जैसे शहर में ऐसी घटना का होना और भी चिंता की बात है क्योंकि यह शहर कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा लिए फिरता है। स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार अव्वल आने वाले शहर में अगर सैंकड़ों लोग दूषित पानी के कारण बीमार पड़ जाएं और उन्हें जीवन-मौत से जूझना पड़े, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वच्छता का अर्थ केवल सड़कों की सफाई और पेंटिंग तक ही सीमित है?

क्या नागरिकों को शुद्ध पेयजल जैसा मौलिक अधिकार देना नगर निगम और प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है? यह त्रासदी हमें इसलिए भी झकझोरती है क्योंकि अन्य शहरों के मुकाबले यहां कहीं अधिक चाक-चौबंद व्यवस्था की अपेक्षा रही है। यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत विफलता का भयावह चेहरा है। जिम्मेदारों पर आपराधिक लापरवाही की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ इंदौर को स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर% के रूप में ग्लोबल ब्रांड बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गरीब बस्तियों के लोग दम तोड़ रहे हैं। ऊपर से राजनीतिक नेतृत्व का यह अहंकार न केवल निंदनीय है, बल्कि यह उस भरोसे का कत्ल भी है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी इस मामले में एक उम्मीद की किरण है। अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रशासन की विफलता को रेखांकित किया है। फौरी तौर पर कुछ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई इस समस्या का समाधान नहीं है। पानी की पाइपलाइनों का ड्रेनेज लाइनों के साथ मिलना या उनमें लीकेज होना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इसकी नियमित निगरानी की कमी एक बड़ा अपराध है। यह घटना केवल इंदौर के लिए नहीं, बल्कि देश के उन तमाम शहरों के लिए एक चेतावनी है जो बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज कर बाहरी सौंदर्योत्थान पर पैसा बहा रहे हैं। जन-स्वास्थ्य किसी भी शहर की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अरावली की परिभाषा में निहित हो संरक्षण का लक्ष्य

प्रो. सुखदेव सिंह

अरावली पहाड़ियां कभी अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ऊंचे वलित पहाड़ों की शृंखला थी जो लाखों साल की टूट-फूट और कटाव से घिसकर ऊंची-नीची पहाड़ियों, चोटियों व चट्टानी उभारों की शृंखला बन गई हैं। ये पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक हैं, कई कम ऊंची भी हैं जबकि राजस्थान के माउंट आबू पठार पर गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1,722 मीटर ऊंचाई तक है। हाल ही में अरावली ने पर्यावरण विशेषज्ञों, समाज और मीडिया का ध्यान खींचा जब किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमओइएफसीसी समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानीय तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली शर्त मंजूर करते हुए एक फैसला सुनाया जिससे सड़कों पर विरोध और बयानबाजी होने लगी।

2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरावली पहाड़ों की एक समान परिभाषा बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें समुद्र तल के बजाय स्थानीय तल आधारित राजस्थान की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया जा सके। राजस्थान की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, समिति ने मानदंड तैयार किए कि पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा मानने के लिए इसकी ऊंचाई आसपास के स्तर से 100 मीटर होनी चाहिए या इसे अरावली शृंखला में दो योग्य पहाड़ियों के बीच 500 मीटर दायरे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को इस परिभाषा को मंजूर कर लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ। सरकार ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए इसे मात्र 'तकनीकी' स्पष्टीकरण बताया और कहा कि राजस्थान में यह 2006 से लागू है व इससे अरावली की हर जगह एक जैसी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचना के भी यही बिंदु हैं। गत 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट

ने सार्वजनिक असंतोष का हवाला देकर 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी। अरावली के लिए टेक्निकल कमेटी द्वारा सुझाई समुद्र तल के बजाय लोकल-एरिया तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली व्याख्या अपने आप में त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक और मनमानी आधारित है, न कि पहाड़ी की ऊंचाई मापने के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक।

यह क्षेत्र ऐसे भी समुद्र तल से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, यानी यहां के स्थानीय स्थल से 99 मीटर ऊंचा पहाड़ समुद्र तल से 199 मीटर ऊंचा होगा



परन्तु टेक्निकल समिति की व्याख्या अनुसार यह पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जायेगा जब तक 100 मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के 500 मीटर दायरे में नहीं आएगा। इससे राजस्थान के 90 फीसदी पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। राजस्थान में 12081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड पूरा करेंगी। समुद्र तल एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डइज्ड रेफरेंस पॉइंट है, जबकि लोकल रिलीफ मनमाना है। दूसरा, राजस्थान में एक परिभाषा है और उसी के अनुसार माइनिंग की अनुमति है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं और माइनिंग पर रोक है। कमेटी ने राजस्थान लीगल कोड में अरावली को परिभाषित कर 'एक समानता' जोड़ी व इसे हरियाणा और अरावली रेंज साझा करने वाले सभी राज्यों में लागू किया, जिससे कानूनन हरियाणा में भी माइनिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति की राह खुलती

है। परिभाषा का घोषित लक्ष्य अरावली में माइनिंग को 'रेगुलेट' करना है, न कि रोकना। दिल्ली और हरियाणा में अरावली में ज्यादा अलग-थलग छोटी पहाड़ियां और चोटियां हैं। यही वह मुख्य बात है जिस पर रियल एस्टेट कारोबारियों की नज़र है, जो गुडगांव व फरीदाबाद जिलों में अपने कार्य को कानूनी रूप देना चाहते हैं, जहां वे किसी न किसी तरह से पहले ही काम कर रहे हैं, जिससे वहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। साल 2023 के एक सर्वे में, इस इलाके में 786 एकड़ ज़मीन पर मंजूरशुदा इमारतों के अलावा,

लगजरी फार्म हाउस, रिसॉर्ट, बैंकवेट हॉल, घर, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान वगैरह के रूप में 6793 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर पाए गए। यह बाजार-संचालित खनन, वनों की कटाई और रियल एस्टेट विकास है जिससे अरावली पहाड़ियों को खतरा है। एक बार जब अरावली के कुछ हिस्सों को उसके दायरे से बाहर रखने के लिए परिभाषित किया जाएगा, तो खनन और रियल एस्टेट कंपनियों को न उस क्षेत्र पर कानूनन कब्जा करने की अनुमति मिल जाएगी; इसके बाद उन्हें अरावली के दिल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। बाजार-संचालित ताकतें इसी तरह काम करती हैं। 'मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने' के मकसद से काम करने वाली बाजार-संचालित ताकतें मानवीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और प्राकृतिक चिंताओं के 'बाहरी प्रभावों' पर ध्यान नहीं देतीं, जिसके चलते प्रदूषण, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होता है।

प्रो. सुखदेव सिंह

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'कारागार बंदियों के मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। एक सत्र में महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील जेल सुधार पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप उनके सार्थक पुनर्वास को सुनिश्चित करने वाली 'महिलाओं के लिए हिरासत में न्याय' पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2023 तक देश की विभिन्न जेलों में 21,510 महिला कैदी और 1492 शिशु बन्द थे। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी माताओं के साथ जेल में रहने की अनुमति है, यदि उनकी देखभाल के लिए बाहर कोई उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध न हो। शिशुओं के साथ उनकी 1318 माताओं में से 1049 विचाराधीन कैदी थी और शेष 249 महिलाएं दोष-सिद्ध महिलाएं थीं।

देश की जेलों में महिला कैदियों की संख्या 4 प्रतिशत है। उनकी कैद मानवाधिकारों से जुड़ी अनेक चिन्ताएं उत्पन्न करती है, विशेषतया उनके बच्चों के सम्बन्ध में। महिला अपराधियों का कारावास न्याय-शास्त्र की दुविधा की ओर भी इशारा करता है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान ही दण्ड प्रक्रिया और सुधारात्मक मानकों के अधीन रखा जाए। महिलाओं का अपराध क्षणिक आवेश की परिणति होता है। महिला सौंदर्य, रचनात्मकता, देखभाल और प्रेम, इच्छा, समृद्धि और सृजन की प्रतिमूर्ति होती है और अपराध-प्रवृत्ति उसके स्वभाव में नहीं है। महिलाओं द्वारा अपराध करने

महिला कैदियों हेतु लिंग संवेदनशील सजा नीति बने



के पीछे के कारणों और उद्देश्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे ऐसा मुख्य रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करती हैं, जब उनके पास अपने बच्चों और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचता है। कभी-कभी, महिलाएं लैंगिक रूप से असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था और नारीत्व को ठेस पहुंचाने वाले मानदण्डों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए भी कानून तोड़ने पर मजबूर होती हैं।

अक्सर, महिला अपराधी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कथित पारिवारिक सम्मान की रक्षा और विरोधियों से बदला लेने के लिए अपराधों में संलिप्त हो जाया करती हैं। लगभग हर स्थिति में, महिला अपराधी परिस्थितियों की शिकार होती हैं। उन्हें अपने दोषपूर्ण पालन-पोषण और प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण की कीमत चुकानी पड़ती है। 80 प्रतिशत से अधिक महिला जेल बन्दिनियां विचाराधीन कैदी हैं। यह विडंबना है कि महिला अपराधियों के साथ पुरुष अपराधियों के समान ही व्यवहार किया जाता है। यह

जोगिन्दर कुमार (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के विपरीत है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि गिरफ्तारियां जरूरत के आधार पर होनी चाहिए। गिरफ्तारियां तभी न्याय-संगत होती हैं जब उन्हें आगे होने वाले अपराधों को रोकने, या अपराध के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया हो कि अपराधी अदालती कार्यवाही से नहीं भागेगा।

महिला अपराधियों की गिरफ्तारी इस दृष्टि से तार्किक नहीं है क्योंकि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति आमतौर पर क्षणिक होती है और आमतौर पर बदले की भावना से प्रेरित नहीं होती। इस प्रकार, विचाराधीन महिलाओं की हिरासत न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा शक्ति का एक उद्देश्यहीन प्रदर्शन ही प्रतीत होती है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखना अनावश्यक है। कोई कारण नहीं है कि महिलाओं को अदालतों द्वारा जमानत पर रिहा न किया जा सके, भले ही उन्हें पुलिस द्वारा बिना सोचे-समझे गिरफ्तार कर लिया गया

हो। लिंग-संवेदनशील सजा-नीति के अभाव में, महिला दोषियों को भी पुरुषों के समान ही दण्डात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है। निःसंदेह, महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से भिन्न होती हैं। सामुदायिक सेवा, सजा से पहले और बाद में परिवीक्षा पर रिहाई, अनिवार्य परामर्श और जुर्माना आदि जैसे गैर-हिरासती सुधार विकल्पों की हकदार हैं। सामाजिकता पर आधारित सुधार-उपाय महिला अपराधिकता के निराकरण के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो सकते हैं। महिलाओं को असाधारण मामलों में ही कैद किया जाना चाहिए, वह भी उनके घरों के पास की जेलों में। प्रत्येक जिला जेल में महिला अपराधियों को रखने के लिए अलग महिला बैरकों की आवश्यकता है।

इन बैरकों की वास्तुकला में स्त्री-उन्मुखता और घर जैसे वातावरण की परिकल्पना होनी चाहिए। महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के 77 प्रतिशत पीड़ित उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति होते हैं, परिणामस्वरूप, महिला कैदियों को आमतौर पर उनके प्रियजनों द्वारा त्याग दिया जाता है। निःसंदेह, जेल में बन्द महिलाओं का जीवन कष्ट-प्रद है, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक भीड़भाड़ वाली बैरकों में बन्द रखा जाता है। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैदीन की बहुत सीमित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 'सैनटरी नैपकिन' और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था असन्तोषजनक है। उन्हें काम के अवसर शायद ही उपलब्ध हों और अकेलापन उनकी नियति बन जाता है। जेल में बन्द अधिकांश महिलाओं के पास धन का अभाव होता है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है।

हाइड्रेटेड

रखने के लिए सर्दियों में इनका करें सेवन

आमतौर पर लोग मानते हैं कि डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मियों की समस्या है, लेकिन सच यह है कि यह परेशानी सर्दियों में भी हो सकती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि डिहाइड्रेशन की समस्या ठंड में उतनी ही खतरनाक होती है, जितनी गर्मी के मौसम में होती है। अक्सर ठंड के कारण हमें प्यास कम लगती है, पसीना कम आता है और हम पानी पीना कम कर देते हैं। इस वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जो थकान, सिरदर्द, रूखी त्वचा और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए सादा पानी के साथ आप कुछ ऐसे तरल पदार्थों और खाद्य पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं जो आपको न सिर्फ हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे, बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें कई ऐसी चीजें दी हैं जिनका सेवन करके हम ठंड में भी खुद को आसानी से हाइड्रेटेड रख सकते हैं।



पानी से भरपूर फल

जैसे फल खाएं, जिनमें पानी की मात्रा 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक होती है। ये फल सिर्फ आपको हाइड्रेटेड नहीं रखते, बल्कि विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होते हैं, जो सर्दियों में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें सीधे खाने या जूस के रूप में लेने से शरीर को तुरंत नमी और ऊर्जा मिलती है। खासतौर से वर्कआउट करने वालों को संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और ये स्किन को हेल्दी बनाता है।

सूप और दाल का पानी

सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए गरमा गरम सूप से बेहतर कुछ नहीं होता। चाहे वह वेजिटेबल सूप हो या चिकन सूप, ये उच्च जल सामग्री वाले होते हैं। सूप में मौजूद सब्जियां और शोरबा एक साथ तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। इसके अलावा दाल का पानी या दाल का पतला शोरबा भी एक बेहतरीन पारंपरिक विकल्प है, जो पोषक तत्वों के साथ-साथ हाइड्रेशन भी प्रदान करता है। इसे रोजाना पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन सब के साथ कोशिश करें कि दिनभर में कम से कम 7-8 गिलास पानी पी लें।



नारियल पानी और हर्बल चाय

सुबह-सुबह एक गिलास ताजा नारियल पानी पीना सिर्फ ताजगी देने वाला नहीं बल्कि सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि सादे पानी के अलावा नारियल पानी सर्दियों में हाइड्रेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। यह प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर पोटेशियम, से भरपूर होता है, जो शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही, हर्बल चाय (जैसे अदरक, तुलसी या कैमोमाइल चाय) भी हाइड्रेशन प्रदान करती है। अच्छी बात यह है कि हर्बल चाय आपको ठंड के दिनों में गर्माहट भी देती है।

खीरा और अन्य सब्जियां

फल ही नहीं, कुछ सब्जियां भी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खीरा, जिसमें लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है, ठंड में डिहाइड्रेशन से लड़ने का एक शानदार तरीका है। खीरा कम कैलोरी वाली सब्जी है जो वेट लॉस में मदद करती है। यह एक शानदार सब्जी है जो वजन कम करने में मदद करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करती है। इसके अलावा, सलाद और अन्य खाद्य पदार्थों में पानी से भरपूर टमाटर और शिमला मिर्च को भी शामिल करें। ये सब्जियां न केवल पानी की आपूर्ति करती हैं, बल्कि भोजन के साथ-साथ आपके तरल पदार्थ के सेवन को भी बढ़ाती हैं।



हंसना मना है

एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था, एक दिन लड़का बोला-आई लव यू, लड़की- अगर मैं भी आई लव यू बोलूं, तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का- जानम, मैं तो खुशी से मर जाऊंगा, लड़की बहुत ही चालाक निकली, तिरछी नजर घुमा के बोली- जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी?

आर्मी ट्रेनिंग के दौरान, अफसर ने पूछा- 'ये हाथ में क्या है?' सुरेश- सर, बन्दुक है! अफसर- ये बन्दुक नहीं! तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी मां है मां ! फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा: ये हाथ में क्या है? रमेश- सर, ये सुरेश की मां है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है मौसी...! सर बेहोश...

काफी दिनों बाद संता पार्क में घूमने गया, घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को बताया जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं, पत्नी- ये तुमने कैसे जाना। संता- जब मैं पार्क में गया था तो वहां पर औरतें मुझे देख कर बोली, हे भगवान!, तू फिर आ गया।

कहानी

राजा और मूर्ख बंदर

बहुत पुरानी बात है, एक राजा के पास पालतु बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था। उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झल रहा था, तभी एक मक्खी भिन भिनाते हुए राज के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार-बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफी समय तक ऐसे ही मक्खी को भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है, तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देख कर राजा काफी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है, तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। इसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है, तो बंदर के तलवार से राजा के बाल कट जाते हैं और जब मूँछ पर बैठती है, तो मूँछ कट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल-पुथल मच जाती है। कहानी से सीख- इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी मूर्ख को ऐसा काम न सौंपे, जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दे।

7 अंतर खोजें



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



मेघ

प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। भाइयों की मदद मिलेगी।



वृषभ

संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी।



मिथुन

रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा।



कर्क

क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुःखद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें।



सिंह

मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। सगे-संबंधी मिलेंगे।



कन्या

मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मान बढ़ेगा। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी।



तुला

यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं।



वृश्चिक

वाणी पर नियंत्रण रखें। विवादों से दूर रहना चाहिए। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें।



धनु

नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी।



मकर

नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पुछ-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।



कुम्भ

कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रुओं से सावधान रहें।



मीन

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है।

सौ रभ हत्याकांड ने देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू-सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में नीले ड्रम वाली खौफनाक हत्या की कहानी समेत राजा रघुवंशी मर्डर केस की झलक भी दिखाई गई है। सीरीज का नाम हनीमून से हत्या है। इसमें वैवाहिक हत्याओं को करीब से दिखाया गया है कि कैसे पत्नियां अपने पतियों की हत्या करती हैं और ऐसा करने के पीछे उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है।

हनीमून से हत्या का टीजर में औरतों की ताकत को दिखाया गया है। टीजर की शुरुआत में बताया गया है कि औरत के कितने अलग रूप हो सकते हैं। एक औरत वक्त पड़ने पर जरूरत के हिसाब के कोई भी रूप ले सकती है।

टीजर की शुरुआत दमदार डायलॉग से होती है, जो है- औरत मां है, औरत बहन है, लक्ष्मी है, सरस्वती है तो काली भी है। डॉक्यू-सीरीज के टीजर वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे शादीशुदा महिलाएं पत्नी से कातिल का रूप लेती हैं। अपने प्यार के लिए वो

सोनम ने राजा रघुवंशी को क्यों मारा, जल्द ही नीले ड्रम की दिखेगी खौफनाक कहानी



पति के कत्ल की साजिश रचती हैं और फिर उसे खौफनाक तरीके से अंजाम देती हैं।

हनीमून से हत्या के टीजर वीडियो में सौरभ हत्याकांड से लेकर को लेकर राजा रघुवंशी मर्डर केस को भी दिखाया गया है। ये भी बताया गया है कि मीडिया और इंटरनेट पर कई अलग कहानियां सामने आई हैं। मगर असल कहानी

इससे काफी हटकर है।

डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इस हत्या के पीछे के काले और भयानक कारणों और अपराधियों की मानसिक स्थिति की गहराई से पड़ताल को दिखाया जाएगा। टीजर देखकर इतना तय है कि इसमें सौरभ हत्याकांड, राजा रघुवंशी की मर्डर समेत कई केसेस की कई अनकही और अनसुनी परतें खुलने वाली हैं, जिनसे

लोग अभी तक अनजान हैं। सीरीज में सिर्फ अपराध को होते हुए ही नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि खुशहाल लगने वाली शायदियों की परतों को खोलकर उनके अंदर छिपे काले रहस्यों से भी दुनिया को रूबरू किया जाएगा।

हनीमून से हत्या तक डॉक्यू सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE-5 पर 9 जनवरी से स्ट्रीम होगी। ये हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। ये सीरीज मेरठ के दिल दहलाने वाले उस हत्याकांड पर आधारित है, जब मुस्कान नाम की एक महिला अपने बॉयफ्रेंड साहिल संग मिलकर पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस हत्याकांड ने देशभर में हड़कंप मचा दिया था। इसके अलावा इसमें राजा रघुवंशी की मर्डर को भी दिखाया जाएगा, जब सोनम नाम की महिला ने शादी के बाद हनीमून पर ले जाकर अपने पति की सुपारी देकर उसकी जान ले ली थी।

क गना रनौत फिल्मों में जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार हैं।

लंबे समय से राजनीतिक जिम्मेदारियों और फिल्मों के बीच संतुलन बनाती नजर आ रही कंगना ने अपनी अगली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की और फिल्म के सेट से कुछ झलकियां भी साझा कीं, जिसे देखकर उनके प्रशंसकों में उत्साह साफ नजर आया।

कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो को रीपोस्ट किया। इस वीडियो में वह फिल्म के सेट पर पहुंचती दिखती हैं और निर्देशक मनोज तापड़िया के साथ गंभीर चर्चा में नजर आती हैं। हाथ में स्क्रिप्ट, चेहरे पर फोकस और काम के प्रति वही

फिल्मों में जबरदस्त वापसी की तैयारी में कंगना रनौत



पुराना जुनून- ये सबकुछ देखकर साफ नजर आ रहा है कि कंगना एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ फिल्मी दुनिया में सक्रिय हो चुकी हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि शूटिंग सेट पर वापस आकर अच्छा लग रहा है।

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को

लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2024 में हुई थी, तब यह बताया गया था कि फिल्म आम लोगों की असाधारण कहानियों पर आधारित होगी। कंगना इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं और फिल्म का मकसद उन

किरदारों को सामने लाना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव की मिसाल बनते हैं।

कंगना की पिछली फिल्म 'इमरजेंसी' काफी चर्चा में रही थी। इस राजनीतिक ड्रामा में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी और फिल्म का निर्देशन भी खुद किया था। हालांकि विषय दमदार होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बावजूद कंगना अपने बेबाक अंदाज और जोखिम लेने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती हैं। इसी बीच कंगना के करियर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। वह जल्द ही हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं।

बॉलीवुड

मन की बात

प्रियंका ने 2026 को बताया भविष्य बोलीं- उम्मीद की किरण जल्दगी



प्रि यंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद ले रही हैं। उन्होंने फैमिली के साथ नए साल का स्वागत किया। अब एक्ट्रेस छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने 2026 को अपना भविष्य बताते हुए खुद को भाग्यशाली बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी इस जिंदगी के लिए भी ईश्वर का आभार जताया है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कुछ वीडियो साझा किए हैं। इन वीडियो में प्रियंका बीच पर नजर आ रही हैं। वीडियो को बनाते हुए एक्ट्रेस ने 2026 का स्वागत किया और ईश्वर का धन्यवाद जताया। कैप्शन में विचार लिखते हुए एक्ट्रेस वीडियो में कहती हैं, 'मैंने खुद से कहा था कि मैं इसमें बेहतर हो जाऊंगी, यानी कैमरे से बात करने में। 2026 में मेरे पहले कुछ कदम। यह भविष्य जैसा लगता है। मैं अपने प्रशंसकों से कहती रही हूँ कि 2026 भविष्य जैसा लगता है। यह कैसे संभव है? लेकिन हम यहां हैं, अपने परिवार को देख रही हूँ, अपने खूबसूरत कदमों को देख रही हूँ और खुद को भाग्यशाली मानकर आभारी हूँ। इतने लंबे समय तक इतनी तेज गति से दौड़ने के बाद, आप खुद को शाबाशी देना भूल जाते हैं कि आप बच गए। तो मैं खुद को शाबाशी दे रही हूँ।' प्रियंका ने स्टोरी पर एक और वीडियो भी साझा किया। दूसरे वीडियो में अपनी बात को जारी रखते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि खुद के प्रति दयालु रहना और इस जीवन को जीने का मौका मिलने के लिए वास्तव में मैं आभारी हूँ। हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर होती है। बस आगे बढ़ते रहो। अब मैं अपने घर की ओर पीछे की ओर चल रही हूँ। वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पहले एपिसोड में नजर आई थीं। इसके अलावा वो अब एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में दिखाई देंगी। बड़े स्तर पर बन रही इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होनी है।

इस गांव में कभी रहते थे 120 नागरिक आज बचा है सिर्फ एक आदमी



अगर आप भारत के किसी गांव में जाएंगे तो वहां आपको इतनी आबादी दिखेगी कि वो आपको गांव नहीं, बल्कि छोटा-मोटा शहर ही लगेगा। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी गांव हैं जो ऐसे नहीं हैं। यहां काफी कम लोग रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सिर्फ 1 आदमी रहता है। पहले कभी यहां पर 120 से ज्यादा नागरिक रहा करते थे। पर अब सिर्फ 1

बचा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कहां चले गए? इंस्टाग्राम यूजर @annainlisbon एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो पुर्तगाल में रहती हैं। वो एक पूर्व टीवी रिपोर्टर हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो पुर्तगाल के एक गांव में पहुंची हैं, जहां सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। इस गांव का नाम तलासनल है जो मध्य पुर्तगाल में पहाड़ियों के बीच बसा गांव है। वहां पर एक बुजुर्ग शख्स रहता है, जिसका नाम जॉर्ज है। महिला ने गांव में जाकर उस शख्स से मुलाकात की जिसने उसे गांव से जुड़ी कई रोचक बातें बताईं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस गांव में जॉर्ज अकेले नागरिक हैं। 1900 के दौर में इस गांव में 120 से ज्यादा लोग रहा करते थे। मगर धीरे-धीरे वे सभी गांव छोड़कर चले गए। कारण ये था कि गांव इतनी दूर, एकांत में बसा था, कि वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं। इस वजह से लोग शहरों में रहने चले गए। 1980 तक सिर्फ 2 नागरिक बचे थे। अब जॉर्ज अकेले रह गए हैं। जॉर्ज का अपना एक बार है। गांव में टूरिस्ट आते हैं और उसी बार में शराब पीते हैं और जॉर्ज की कहानियां सुनते हैं। सिर्फ जॉर्ज का ही घर ऐसा है जहां मेल बॉक्स है। इस वीडियो को 51 लाख व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने कहा कि वो इस जगह पर गई है और उसे ये जादुई जगह लगती है। एक ने कहा कि गांव जरूर खूबसूरत है मगर रात में यहां बहुत डर लगता होगा। एक ने कहा कि उसने यहां पर एक पूरा घर किराये पर लिया था।

अजब-गजब

इस शहर को कहा जाता है आइस सिटी

यहां होती है बर्फ की खेती! ट्रक में लादकर ले जाते हैं 'फसल'!

चीन में बर्फ की खेती होती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हरबिन शहर में ये हकीकत है। सर्दियों के आगमन पर सोंगहुआ नदी पूरी तरह जम जाती है और यहां मजदूर बर्फ की 'फसल' काटते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां सैकड़ों मजदूर लाल कोट पहने, चाकू, हथौड़े और मशीनों से नदी की जमी सतह पर ग्रिड बनाते नजर आ रहे हैं। फिर बर्फ को बड़े-बड़े ब्लॉक्स में काटकर ट्रक में लाद कर ले जाते हैं। लेकिन आखिर ये मेहनत की क्यों जाती है। आइये आपको बताते है पूरा मामला। ये सब हरबिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल के लिए होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार विंटर फेस्टिवल है। हरबिन, चीन के उत्तर-पूर्वी प्रांत हेलोंगजियांग की राजधानी है, जिसे 'आइस सिटी' कहा जाता है। यहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सोंगहुआ नदी 4-5 महीने तक जम जाती है। हर साल दिसंबर की शुरुआत में 'आइस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल' शुरू होता है। 7 दिसंबर 2025 को छठा आइस कलेक्टिंग फेस्टिवल शुरू हुआ, जहां 'पहली बर्फ' की कटाई रस्म के साथ की गई। मजदूर पहले नदी पर ग्रिड मार्क करते हैं, जो लगभग 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े होते हैं। फिर स्विंग साँ या मोटराइज्ड साँ से इन्हें काटते हैं। ब्लॉक्स की



मोटाई 30-60 सेमी होती है और वजन 400-700 किलो तक। ये काम खतरनाक होता है। मजदूरों को लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है, क्योंकि बर्फ टूटने पर वो पानी में गिर सकते हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी आइस हार्वेस्टिंग की जाती है।

20-30 दिनों में हजारों क्यूबिक मीटर बर्फ काटी जाती है। फिर इन्हें क्रेन या कन्वेयर बेल्ट से नदी किनारे लाते हैं, ट्रकों में लोड कर स्टोरेज या सीधे फेस्टिवल साइट पर ले जाते हैं। कुछ ब्लॉक्स को साल भर स्टोर किया जाता है। इसके लिए इन्हें भूसे और सफेद कवर से ढककर रखा

जाता है ताकि अगले साल पहले से निर्माण शुरू हो सके। ये बर्फ हरबिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल होती है, जो फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण है। यहां विशाल आइस महल, पुल, स्लाइड, टावर और मूर्तियां बनती हैं। सब LED लाइट्स से जगमगाती हैं। फेस्टिवल दिसंबर के अंत से फरवरी तक चलता है और 1.8 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इसे अटेंड करने आते हैं। 2025-2026 सीजन में 1.2 मिलियन स्केयर मीटर क्षेत्र में फैला पार्क, 4 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ-स्नो से बनाया गया है। थीम एशियन विंटर गेम्स से जुड़ी है।

भाजपा हेलिकॉप्टर रोक सकती है हौसले नहीं

» टीएमसी सांसद बोले- एसआईआर के जरिए बीजेपी ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी है

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि जब वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बीरभूम के रामपुरहाट जा रहे थे, तब भाजपा ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन भाजपा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। भाजपा सोचती है कि इन चालों से मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं भाजपा से दस गुना ज्यादा जिद्दी हूँ।

बनर्जी ने आगे दावा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ली मदद

उड़ान भरने की अनुमति नहीं देने पर अभिषेक बनर्जी बिफरे

बात करने और झारखंड सरकार की मदद से उनके लिए सभा स्थल तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई।

उन्होंने कहा, चूंकि मेरे हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और इस सभा के लिए उनके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तृणमूल कार्यकर्ता के रूप में सभा स्थल पर पहुंचूंगा और अगर वहां दस लोग भी मौजूद हों तो उन्हें संबोधित करूंगा। मैंने देखा कि देर होने के बावजूद, माताएं और बहनें बड़ी संख्या में न केवल इस मैदान पर, बल्कि बाहर भी आई हैं। मैं उनका आभारी हूँ। बनर्जी ने

भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी एक सांप की तरह है जो अगर रहने दिया जाए तो डंक मार देगी। आगामी चुनावों से पहले अपने अबर जीत बे बांग्ला अभियान के दौरान अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने मतदाताओं से कतार में खड़े होकर ईवीएम के जरिए भाजपा को सबक सिखाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, भाजपा एक सांप की तरह है। चाहे आप अपने घर के पीछे एक सांप रखें या अठारह, अंततः वह आपको काट ही लेगा। इस बार आगामी चुनावों में यह सुनिश्चित करें कि अलीपुरद्वार में कोई सांप न रहे। मैं भाजपा से दस गुना ज्यादा जिद्दी हूँ, और इस तरह के व्यवहार के आगे केवल भाजपा ही झुकती है। आगामी चुनावों में कतार में खड़े होकर उन्हें ईवीएम के जरिए सबक सिखाएं।

डराने-धमकाने से मैं डरने वाला नहीं : प्रियांक खरगे

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर उनकी टिप्पणियों के लिए उन्हें नोटिस जारी किए जाने की खबरों को खारिज करते हुए इसे संगठन के बारे में जायज सवाल उठाने वालों के खिलाफ डराने-धमकाने की रणनीति बताया। खरगे ने कहा कि वे डराने-धमकाने की रणनीति अपना रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हम आरएसएस, उसके वित्तपोषण और उसके अस्तित्व के बारे में जायज सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप व्यक्तियों का एक समूह है, मुझे देश का एक भी नियम दिखाइए

जो कहता है कि आपका पंजीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जवाबदेही देश के सभी संस्थानों पर लागू होती है। प्रियांक खरगे ने आगे कहा कि जिस देश में मंदिरों को जवाबदेह ठहराया जाता है, गैर-सरकारी संगठनों को जवाबदेह ठहराया जाता है, व्यक्तियों के अन्य संगठनों और संस्थाओं को जवाबदेह ठहराया जाता है, वह आरएसएस को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? ऐसा होने वाला है... भारत में संविधान अभी भी जीवित है। आरएसएस संविधान से ऊपर नहीं है, न ही मैं। आज सुबह, खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख साझा किया, जिसमें बताया गया था कि एक आरएसएस सदस्य द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में एक विशेष अदालत ने उन्हें और राज्य मंत्री दिनेश गुंडुलाओ को नोटिस जारी किया है।

अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में आधी रात को बिगड़ी तबीयत

» सीने में तेज दर्द के कारण मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती

4पीएम न्यूज नेटवर्क देवरिया। जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत मंगलवार की रात अचानक खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उनकी स्थिति सामान्य है। रात के 11:30 बजे पूर्व आइपीएस ने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें आनन-फानन में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लाया गया जहां किसी हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं होने की वजह से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है।

फर्जी ढंग से कूट रचना कर जमीन बेचने के आप में पूर्व आइपीएस जेल में निरुद्ध है। जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ल ने बताया कि पूर्व आइपीएस ने सीने में दर्द बताया था। जिससे उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है उनकी स्थिति सामान्य है। वह चल फिर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं। पूर्व आइपीएस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आइसीयू वार्ड नंबर 14 के बेड नंबर आठ पर भर्ती हैं। सीने में दर्द की वजह से डॉक्टरों ने ट्रॉप आई कि जांच लिखी है। उन्होंने हायर सेंटर रेफर के लिए व्यक्तिगत अनुरोध किया है, लेकिन ट्रॉप आई कि जांच रिपोर्ट न आने से डॉक्टरों ने उन्हें रेफर नहीं किया है। प्राचार्य डॉ. राम कुमार जायसवाल ने बताया कि सीने में दर्द हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, इसलिए ट्रॉप आई कि जांच कराई जा रही है। उनकी तबीयत स्थिर है। उपचार कर रहे डॉ. राजकिशोर सिंह ने बताया कि उनकी ईसीजी जांच कराई गई है जो खराब आयी है। इसलिए कार्डियोलॉजी में रेफरेंस भेजा गया है। ईको जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। तब तक ट्रॉप आई कि जांच रिपोर्ट भी आ जायेगी।

सोनिया को वोटर लिस्ट मामले में राहत

» कांग्रेस नेता को इस मामले में देना है कोर्ट को जवाब

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली की राजज एवेन्यू कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उस याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें मतदाता सूची में कथित जालसाजी के जरिए उनका नाम शामिल किए जाने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसमें आरोप की जांच से इनकार कर दिया गया था। आरोप के मुताबिक 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले ही सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था। स्पेशल जज विशाल गोपने ने सोनिया की ओर से पेश वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

स्पेशल जज ने बीते साल 9 दिसंबर को इस याचिका पर सोनिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। यह रिवीजन



याचिका राजज एवेन्यू कोर्ट के 'सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन' के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दायर की है। एडवोकेट विकास त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने मैजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। याचिका में विकास त्रिपाठी ने 'जालसाजी और धोखाधड़ी' का दावा किया है। शिकायतकर्ता को चेतावटी हुए अदालत ने

राहुल 19 जनवरी को तलब

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एक अदालत ने बुधवार को राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित मानहानि मामले में पेश होने के लिए तलब किया। सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में विपक्ष के नेता को गवाही देने के लिए बुलाया है। यह मामला आठ साल पुराना है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से संबंधित है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर मंगलवार को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई हुई। लगभग 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है और उन्हें 19 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सांसद के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी कर ली है। वकील के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि राम चंद्र दुबे का बयान पूरा हो चुका है। विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

कहा था कि जो सीधे नहीं किया जा सकता, वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। महज बीएनएस 2023 के तहत अपराधों को जोड़ने मात्र से इस अदालत के संवैधानिक प्राधिकारों में किसी भी दखल को उचित नहीं ठहराया जाएगा।

आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम!

» कहा- भारत में विश्वकप खेलो या अंक गंवाओ

4पीएम न्यूज नेटवर्क

दुबई। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच मंगलवार को हुई वरुअल बैठक के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद गहरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने बीसीबी को साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा कारणों के आधार पर बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की मांग खारिज की जाती है। आईसीसी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को भारत आकर खेलना होगा, नहीं तो उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश को लीग राउंड में भारत में चार मैच खेलने थे। हालांकि, बीसीबी ने ऐसे किसी अल्टीमेटम से इनकार किया है। बोर्ड का

कहना है कि आईसीसी की ओर से भारत में खेलो या अंक गंवाओ जैसा कोई संदेश नहीं दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बैठक के बाद न तो बीसीसीआई और न ही बीसीबी ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया, जिससे भ्रम और बढ़ गया है। (यह 20 टीमों का टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से आठ मार्च तक खेला जाना

है। बांग्लादेश ग्रुप सी में है और उसके पहले तीन मुकाबले कोलकाता में तय हैं। सात फरवरी को वेस्टइंडीज, नौ फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ खेला जाना है। यह भी बताया गया कि इस मुद्दे पर आईपीएल गवर्निंग कार्सिल को कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। ऐसे में फैसला किसने लिया, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने कड़ा रवैया अपनाते हुए भारत में होने वाले अपने टी20 विश्वकप के

टी20 विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान

वेलिंगटन। आगामी टी20 विश्वकप के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो चुका है। तेज गेंदबाज जैकब डफी को भी 15 सदस्यीय अनुभवी ब्लैकफैस टीम में शामिल किया गया है। 31 वर्षीय डफी इस टीम में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार सीनियर वर्ल्ड कप खेलेंगे। यह टूर्नामेंट अगले महीने भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की यह टीम कुल 1064 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव रखती है। टीम की कप्तानी मिचेल सैंटनर करेंगे, जो अपने करियर का नौवां सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। डफी मौजूद समय में आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। तेज गेंदबाजी विभाग में डफी के साथ लोकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी और एडम मिलने शामिल हैं, जबकि जिमी नीशम तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। स्पिन विकल्पों में ईश सोढ़ी के अलावा माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं।

मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

शहर में जाम, लोग परेशान, प्रशासनिक व्यवस्था नाकाम

» बड़े दफ्तरों की भीड़, सिंगल रोड का बोझ, हर बार कटघरे में वर्दी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



कार्यालय, कचहरी, कैसरबाग बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े-बड़े सरकारी संस्थान स्थित हैं। एक ही सिंगल रोड पर इतनी भारी

आवाजाही, ऊपर से सड़क की सीमित चौड़ाई और नो पार्किंग के बावजूद बेतरतीब खड़े वाहन—ये सभी मिलकर जाम को स्थायी

समस्या बना चुके हैं। इसके बावजूद समाधान के नाम पर सिर्फ तात्कालिक इंतजाम ही दिखाई देते हैं। चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी और ट्रैफिक सिपाही पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक संभालते नज़र आते हैं। जनता को भी उम्मीद रहती है कि चौराहे पर पुलिस खड़ी है तो रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जाम की जड़ सड़क पर नहीं, बल्कि सिस्टम में है। ऐसे में सवाल यह है कि जब समस्या प्लानिंग और व्यवस्था की है, तो कार्रवाई हर बार नजदीकी चौकी इंचार्ज या सिपाही पर ही क्यों होती है?

यह वही रूट है जो परिवर्तन चौराहे से सीधे मेडिकल कॉलेज, दुबग्गा चौक, बालागंज, मलिहाबाद और हरदोई रोड को

जोड़ता है। सिंगल रूट होने के कारण यहां थोड़ी सी भी अव्यवस्था पूरे शहर के ट्रैफिक को प्रभावित कर देती है। सड़क को चौड़ा करने, वैकल्पिक रूट विकसित करने या बड़े कार्यालयों के लिए अलग पार्किंग और ट्रैफिक प्लान बनाने पर अब तक गंभीरता से काम नहीं हुआ। आला अधिकाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जाम के मूल कारणों पर ध्यान दें। सिर्फ फील्ड में खड़े पुलिसकर्मियों पर दबाव डालना या कार्रवाई करना समाधान नहीं है। जरूरत है परिवहन विभाग, कचहरी प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के बीच समन्वय की, ताकि इस रूट के लिए स्थायी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार हो सके।

भारत सरकार में कूटनीतिक दृष्टिकोण की कमी : गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की निंदा की

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की निंदा की और पड़ोसी देश के प्रति भारत सरकार के कूटनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना की। एक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही बर्बरता की खबरों को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि पांच हिंदुओं की हत्या और महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार मानवता पर कलंक हैं।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को याद करते हुए, गहलोत ने बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और इसे भारत सरकार की कूटनीति की विफलता बताया। गहलोत ने कहा, बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही बर्बरता की खबरें चिंताजनक हैं। महज 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या और वहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार मानवता पर कलंक हैं। 1971 के उस दौर की यादें आज भी ताजा हैं, जब श्रीमती



इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने न केवल कूटनीतिक दृढ़ता दिखाई, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया। उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति की भी परवाह नहीं की, जिसने भारत के खिलाफ अपना सातवां बड़ा भेजा था। यह भी चिंताजनक है कि

प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जीवन और गरिमा की रक्षा करना भारत का नैतिक और कूटनीतिक दायित्व है। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार को गहरी चिंता व्यक्त करने जैसे औपचारिक बयानों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने चाहिए। पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और गरिमा की रक्षा करना हमारा नैतिक और कूटनीतिक दायित्व है। इतिहास गवाह है कि निर्दोषों की जान केवल खोखले नारों से नहीं, बल्कि निर्णायक नेतृत्व से बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर प्रभावी दबाव डालना चाहिए।

जिस देश के निर्माण में भारत ने ही मदद की थी, वह भारत के खिलाफ हो गया है। यह भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है।

संस्था को बदनाम करने और छात्रों के उत्पीड़न को तेज करने का एक संगठित प्रयास किया जा रहा : जेएनयूएसयू

» छात्र संघ ने दिल्ली पुलिस पर भी साधा निशाना

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने मंगलवार को परिसर में लगाए जा रहे भड़काऊ नारों को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था को बदनाम करने और छात्रों के उत्पीड़न को तेज करने का एक संगठित प्रयास किया जा रहा है।

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जाने की घटना के बारे में बात करते हुए, जेएनयूएसयू ने कहा कि परिसर में जनवरी 2020 में हुई हिंसा के विरोध में 5 जनवरी को एक कैंडल मार्च निकाला गया था। जेएनयूएसयू के बयान में कहा गया कि 5 जनवरी 2020 को, नकाबपोश हथियारबंद गुंडों ने जेएनयू परिसर में घुसकर साबरमती हॉस्टल और अन्य इलाकों में छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। यह कोई मामूली



कोमल शर्मा और एबीवीपी के वे गुंडे अब तक नहीं पकड़े गए

बयान में आगे कहा गया कि कोमल शर्मा और एबीवीपी के वे गुंडे कहां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की बात स्वीकार की थी? दिल्ली पुलिस—जो लोकतांत्रिक प्रतिरोध के छोटे से छोटे कृत्यों के लिए भी जेएनयूएसयू पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में असाधारण दक्षता दिखाती है—5 जनवरी के मामले में एक भी गिरफ्तारी करने में विफल रही है। 5 जनवरी 2020 को, छात्रावास शुल्क वृद्धि के विरोध में कैंपस में हो रहे प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष पर हमला कर दिया था। कुछ दिनों बाद, हमलावरों के साथ एक अज्ञात महिला देखी गई, जिसकी पहचान कोमल शर्मा के रूप में हुई। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समुदाय पर खुला हमला था जो शांतिपूर्वक फीस में भारी बढ़ोतरी का विरोध कर रहा था, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। उस आतंक भरी रात को छह साल बीत चुके हैं।

यूपी में भीषण ठंड से घरों में दुबके लोग 31 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर चल रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने 7 जनवरी को 31 जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी है।

यूपी में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों संभागों में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है जबकि कहीं-कहीं शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। कई जगहों



पर विजिबिलिटी जीरो मीटर रहने का अनुमान है। घने कोहरे की वजह से लोग सुबह और शाम के समय घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नटा छाया है और दूर-दूर तक कोहरे की सफेद परत दिख रही है। ठंड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है तो कहीं समय में बदलाव किया गया है।

स्ट्रीट डॉग पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट बोला कुत्तों का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि कब काटेगा

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई जारी है। इस दौरान पीठ ने कहा है कि ये कहा नहीं जा सकता कि कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट लें। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विष्णु नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया कर रहे हैं।

7 नवंबर को न्यायालय ने स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों से सिर्फ रेबीज ही नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना का भी खतरा बढ़ जाता है।

सभी कुत्तों को पकड़ना समाधान नहीं : सिब्लल



डॉग लवर्स की ओर से पेटोकारी कर रहे वकील कपिल सिब्लल ने कहा, सभी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है। आर्थिक रूप से भी यह व्यवहार्य नहीं है। मनुष्यों के लिए भी खतरनाक है। इसे वैज्ञानिक तरीके से ही करना होगा। समस्या यह है कि कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। सिब्लल ने कहा, सभी कुत्तों को पकड़ना समाधान नहीं है।

जिन राज्यों ने जवाब नहीं दिया है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे : जस्टिस संदीप मेहता

इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने जवाब देते हुए कहा, शेकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। जस्टिस मेहता ने कहा, हम केवल यह निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नियमों और कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, जो अभी तक नहीं हुआ है। जिन राज्यों ने जवाब नहीं दिया है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।

